

तेहरान ने समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काटने की धमकी दी

ट्रंप ने ईरान को फिर दी हमले की चेतावनी



वॉशिंगटन/तेहरान, एजेंसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई है। शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका एक और सीमित सैन्य अभियान चला सकता है। उन्होंने इसका नाम ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ बताया। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के

खिलाफ इसी नाम से सैन्य अभियान शुरू किया था। हालांकि, ट्रंप ने संभावित हमले की तारीख या उसके स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध को जल्दी समाप्त कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे पूरी तरह खत्म किया जाए या धीरे-धीरे कमजोर पड़ने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज

जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही जारी है। इस बीच, ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो वह खाड़ी क्षेत्र में समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल को निशाना बना सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान के दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ऐसी स्थिति में केबल

► **ईरान बोला- बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो जवाब देंगे, तनाव बढ़ने से इंटरनेट, बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका**

को नुकसान पहुंचाने और उनकी मरम्मत में बाधा डालने की योजना पर विचार किया जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख यदुल्लाह जवानी ने भी कहा था कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला होने की स्थिति में होर्मुज के नीचे से गुजरने वाली सात प्रमुख इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी अधिकारी मोहसिन रजाई ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े आंकड़ा केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित सुविधाओं पर हमले की चेतावनी भी दी है। समुद्र के नीचे बिछी केबल दुनिया के इंटरनेट संचार की रीढ़ हैं। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अनुसार, वैश्विक इंटरनेट यातायात का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं केबलों से गुजरता है। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक होर्मुज क्षेत्र से दुनिया की एक प्रतिशत से भी कम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट क्षमता

भारतीय पनडुब्बियाँ अब लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी

► **स्वदेशी तकनीक से बढ़ेगी नौसेना की ताकत, पनडुब्बियों के लिए नई प्रणाली का दूसरा चरण शुरू**



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी के भीतर रहने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित स्वदेशी वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली के ऊर्जा मांड्यूल के दूसरे चरण की शुरुआत शनिवार को गुजरात के हजीरा स्थित लार्सन एंड टुब्रो के भारी अभियांत्रिकी परिसर में हुई। इस प्रणाली को नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य डीजल-विद्युत पनडुब्बियों की वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करना है, ताकि वे लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकें। सामान्य पनडुब्बियों को बैटरियां चार्ज करने के लिए सभ्य-सभ्य पर सतह के करीब आना पड़ता है। इससे उनके दूसरे पक्ष की निगरानी में आने का खतरा बढ़ सकता है। नई प्रणाली इस आवश्यकता को कम करके पनडुब्बियों की गोपनीयता और संचालन क्षमता बढ़ाने में मदद

करेगी। रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने इस चरण का उद्घाटन आभासी माध्यम से किया। भारतीय नौसेना के सामग्री प्रमुख वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार और संगठन के नौसैनिक प्रणालियों एवं सामग्री महानिदेशक डॉ. आर. बालमुरलीकृष्णन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सिंह ने वैज्ञानिकों, उद्योग भागीदारों और नौसेना के सहयोगी की सराहना की। उन्होंने हाइड्रोजन तथा ईंधन-कोशिका तकनीक से जुड़े सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। अगले चरण में ऊर्जा मांड्यूल

को बिजली उत्पादन के लिए चालू किया जाएगा। इसके बाद भारतीय नौसेना के निर्धारित मानकों के अनुसार कठोर परीक्षण किए जाएंगे। परीक्षण सफल होने पर मांड्यूल को माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को सौंपने की योजना है, ताकि इसे 2027 की शुरुआत में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में लगाया जा सके। यह परियोजना स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने के प्रयासों का अहम हिस्सा है। इसके सफल होने से भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बियों की जलमग्न क्षमता बढ़ाने और समुद्री अभियानों में उनकी उपयोगिता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब की मदद नहीं करेगा तुर्किये



► **रक्षा मंत्री यासर गुलर बोले- हमारा उद्देश्य सऊदी की सुरक्षा मजबूत करना**

अंकारा/रियाद, एजेंसी: तुर्किये ने स्पष्ट किया है कि वह हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब की ओर से सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। तुर्किये के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनके देश का उद्देश्य सऊदी अरब की सुरक्षा मजबूत करना और उसके दुश्मनों को हमला करने से रोकना है। गुलर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अगस्त में तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों

देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि, तुर्किये के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि समझौते के बावजूद हूती विद्रोहियों के विरुद्ध सैन्य अभियान में उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी। इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका भी सऊदी अरब की ओर से मांगी गई सैन्य सहायता को लेकर पीछे हट चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि उसकी सेना किसी दूसरे देश की धरती पर युद्ध में शामिल नहीं होगी। इससे सऊदी अरब को क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में अपेक्षित सैन्य समर्थन मिलने को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधे सैन्य हमले की मांग की थी।

जदयू ने अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निकाला

नईदुनिया ब्यूरो, पटना: जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा से विधायक अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निकाला कर दिया है। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

पार्टी के अनुसार, अनंत सिंह लगातार संगठन की नीतियों के विपरीत बयान दे रहे थे। उन पर वरिष्ठ नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और विधान परिषद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने का आरोप है। उन्होंने जनसुराज के प्रयाशी के समर्थन में भी प्रचार किया था। जदयू ने अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी पार्टी से छह साल के लिए निकाला कर दिया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में समाप्त कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार विस अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है। हालांकि, सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को लेना है।

पाकिस्तान में गैस सिलेंडर के दाम 8,200 तक पहुंचे, ईरान सीमा बंद होने से संकट

आपूर्ति रुकने से रसोई गैस की कमी, सैकड़ों टैंकर और मालवाहक वाहन सीमा पर फंसे



इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान में ईरान के साथ सीमा चौकियां बंद होने के बाद रसोई गैस का संकट गहरा गया है। 12 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत कुछ ही दिनों में 4,500 पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर अलग-अलग शहरों में

7,000 से 8,200 रुपये तक पहुंच गई है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि आपूर्ति बाधित रहने पर कीमतें और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर को ईरान के साथ गन्ध-रिमदान और तपतान सीमा चौकियों को बंद कर

दिया था। बलूचिस्तान सरकार ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताओं और तस्करी रोकने का तर्क दिया, जबकि ईरान ने तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया। सीमा बंद होने से ईरान से आने वाली गैस की आपूर्ति रुक गई।

ईरान से प्रतिदिन आती थी हजारों टन गैस

पाकिस्तान प्रतिदिन ईरान से लगभग 7,000 मीट्रिक टन रसोई गैस आयात करता है। इसमें से 4,000 टन से अधिक गैस गन्ध-रिमदान सीमा मार्ग से आती थी। पाकिस्तान अपनी सालाना रसोई गैस की जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत आयात से पूरा करता है।

ऐसे में सीमा बंद होने से बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतों में तेजी आई। बलूचिस्तान में 12 किलोग्राम का सिलेंडर करीब 7,000 रुपये, लाहौर में 7,500 रुपये और स्करू में 8,200 रुपये तक बिक रहा है। कुछ क्षेत्रों में प्रति किलोग्राम गैस की कीमत भी लगभग दोगुनी हो गई है। इससे आम परिवारों के रसोई खर्च पर दबाव बढ़ा है।

सीमा पर फंसे सैकड़ों वाहन

सीमा बंद होने के कारण गैस से भरे टैंकरों समेत सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे हुए हैं। आलू, केले और चावल लेकर ईरान जा रहे पाकिस्तान के एक हजार से अधिक मालवाहक डिब्बों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। गन्ध-रिमदान मार्ग को बुधवार को खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए फिर खोला गया, लेकिन गैस का आयात अब भी बाधित है। व्यापारियों और गैस कारोबार से जुड़े संगठनों ने चेतावनी दी है कि सीमा पर रुकावट लंबे समय तक जारी रहने पर कमी और बढ़ सकती है। सर्दियों में गैस की मांग बढ़ने से स्थिति और कठिन होने की आशंका है। पाकिस्तान और ईरान के अधिकारी व्यापार फिर शुरू करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपूर्ति सामान्य नहीं हुई है।

फ्रांस में महंगाई के खिलाफ फिर प्रदर्शन, 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात

► **हिंसा और लूटपाट के बाद कई राहों में कर्फ्यू, राष्ट्रपति मैक्रों ने छात्र संगठनों से की मुलाकात; फुटबॉल मुकाबला टला**



पेरिस, एजेंसी: फ्रांस में महंगाई, बढ़ती लागत और सरकारी सुविधाओं में कटौती के खिलाफ शनिवार को एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और लूटपाट को देखते हुए सरकार ने देशभर में करीब 70 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत विशेष पुलिस दल, लगभग 20 बखराबंद वाहन और पानी की बौछार करने वाले 15 वाहन भी

लगाए गए हैं। पिछले शनिवार को पांच लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई तथा कई वाहनों में आग लगा दी गई। अब तक 2,700 से अधिक लोगों

को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी अनुमान के अनुसार, पिछले सप्ताहांत कम से कम तीन हजार दुकानों को नुकसान पहुंचा या उनमें लूटपाट हुई। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कई शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया

है और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पेरिस में कर्फ्यू सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। मार्सेई और लियोन में शनिवार को जमावड़े पर रोक रहेगी। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन पर भी पारबंदियां लगाई

गई हैं। पेरिस का लुव्र संग्रहालय बंद रहेगा, जबकि पेरिस सेंट-जर्मेन और लियोन के बीच होने वाला फुटबॉल मुकाबला भी स्थगित कर दिया गया है।

राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर शुरू हुए आंदोलन के बाद यह छात्र संगठनों के साथ उनकी पहली सीधी बैठक थी। मैक्रों ने सप्ताहांत में केवल श्रमिक संगठनों के प्रदर्शनों को अनुमति देने की बात कही थी। इससे नाराज प्रमुख छात्र संगठन नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रतिबंध के बावजूद रैली निकालने की घोषणा की है। संगठन का आरोप है कि सरकार

प्रदर्शन करने के अधिकार को सीमित कर रही है।

प्रदर्शन अब स्कूलों की स्थिति से आगे बढ़कर महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और सरकारी सुविधाओं में कटौती के विरोध में बदल गया है। पेरिस, बोर्डों और अन्य शहरों में दुकानों, बैंकों तथा सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। मध्य फ्रांस के लिमोज शहर में 19वीं सदी की ऐतिहासिक नगर परिषद की इमारत में भी आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने हिंसा से प्रभावित कारोबारियों को कर में राहत और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार के सामने अब सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है।

अपराधियों और आतंकियों के नए हथियार बने ड्रोन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्व एशिया में सस्ते ड्रोन अपराधियों और आतंकी संगठनों के लिए नया हथियार बनते जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी, जेलों में प्रतिबंधित सामान पहुंचाने, सैन्य ठिकानों की निगरानी और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, क्षेत्र के सात देशों में ड्रोन से जुड़ी अवैध गतिविधियों के मामले सामने आए हैं। अगस्त 2026 तक दर्ज मामलों में 86 प्रतिशत नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित थे। थाईलैंड में 4,583 ड्रोन जब्त किए गए,

जबकि मलेशिया में 2024 के दौरान ड्रोन से जेलों में नशीले पदार्थ पहुंचाने के 55 मामले सामने आए। म्यांमार में सशस्त्र संगठनों ने 600 स्थानों पर 2,100 ड्रोन हमले किए। इंडोनेशिया में पोप फ्रांसिस की यात्रा के दौरान सितंबर 2024 में हमले की साजिश के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से छोटा ड्रोन मिला था। जांच में इंडोनेशिया से सीरिया में हयात तहरीर अल-शाम से जुड़े लड़ाकों तक ड्रोन और उनके पुर्जे भेजने की कोशिश का भी पता चला। उपकरण इंटरनेट के माध्यम से खरीदे गए थे।

फुकेट से कोलकाता आ रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी



नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: फुकेट से कोलकाता आ रहे विमान के शौचालय में बम से उड़ाने की धमकी का संदेश मिलने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद विमान को अलग स्थान पर ले जाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बम

निरोधक दल और हवाई अड्डा पुलिस ने विमान की सघन तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी भरे संदेश के कारण हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हवाई अड्डे पर दो दिनों में बम की धमकी मिलने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले शुक्रवार को महिलाओं के शौचालय में हाथ से लिखा एक नोट मिला था।

इच्छाशक्ति

बारिश का पानी पीकर और समुद्री जीव खाकर बचाई जान...

समुद्र में अकेले लड़ी 438 दिनों तक जिंदगी की जंग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रशांत महासागर में 438 दिनों तक छोटी नाव पर भटकने वाले मछुआरे सल्वाडोर अल्वारेगा की कहानी संघर्ष, साहस और जीवित रहने की अदम्य इच्छाशक्ति की मिसाल है। एल सल्वाडोर के रहने वाले अल्वारेगा मछली पकड़ने निकले थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान ने उनकी यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा में बदल दिया। भूख, थ्यास, अकेलेपन और अपने साथी की मौत का सामना करने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। नवंबर 2012 में अल्वारेगा अपने 22 वर्षीय साथी इजेकिएल कॉर्डोबा के साथ मेक्सिको के तट से मछली पकड़ने निकले थे। दोनों का इरादा अगले दिन लौटने का था। हालांकि, समुद्र में मौसम बिगड़ने से उनकी नाव दूर बहने लगी। नाव का ईंधन बंद हो गया और रेडियो से संपर्क भी टूट गया। इसके बाद दोनों खुले समुद्र में फंस गए, जहां दूर-दूर तक केवल पानी दिखाई देता था।



समुद्र में जीवित रहने के लिए अल्वारेगा ने मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी पकड़कर खाना शुरू किया। पीने के पानी के लिए वे बारिश पर निर्भर थे। बारिश होने पर वे पानी इकट्ठा करके सभालकर रखते थे, ताकि कई दिनों तक काम चल सके। तेज धूप, बदलते मौसम और पानी की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। इसके बावजूद उन्होंने समुद्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर जीवन बचाने का प्रयास जारी रखा। कुछ समय बाद उनके साथी कॉर्डोबा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी और भोजन की कमी के कारण उनकी हालत लगातार खराब होती गई। अल्वारेगा ने उन्हें सभालने की कोशिश की, लेकिन अंततः कॉर्डोबा की मृत्यु हो गई। साथी को खाने के बाद अल्वारेगा पूरी तरह अकेले रह गए। इस घटना ने उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचाया, फिर भी उन्होंने जीवित रहने की कोशिश नहीं छोड़ी।

438 दिन बाद दिखाई दी जमीन

समुद्र में महीनों तक भटकने के बाद 30 जनवरी 2014 को अल्वारेगा को दूर एक द्वीप दिखाई दिया। उनकी नाव उन्हें प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीपसमूह के एबोन एटोल तक ले आई। वे किसी तरह तट तक पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और सहायता दी। करीब 438 दिनों तक समुद्र में रहने के बाद उनका बचन दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अल्वारेगा अपने घर लौटे और अपनी बेटी फातिमा से मिले। उनके लिए यह भावुक क्षण था। समुद्र में बिताए लंबे समय ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया था। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण बनी कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और जीवित रहने की इच्छा इंसान को संघर्ष जारी रखने की ताकत दे सकती है।

